

(c) if so, what are the details thereof stating—

(i) the annual killings of tuskers since 1980;

(ii) the estimated value of the tusks poached since 1980; and

(d) whether Government propose to launch project elephant on the lines of project tiger to save the elephants population?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (c) The information is being collected and would be placed on the Table of the House.

(a) Yes sir,

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय योजना के अधीन सड़कें तथा पुल

786. श्री राधा किशोर मालवीय : क्या जल-मत्तल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय योजना के अधीन कितनी सड़कें तथा पुल हैं तथा वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी सड़कों तथा पुलों की मंजूरी दी गई है; और

(ख) इस संबंध में मध्य प्रदेश को दी जाने वाली सहायता का व्यौरा क्या है ?

जल-संचारण मंत्री, साथ में जल-मत्तल परिवहन मंत्रालय का प्रतिरित्त प्रसार (श्री मन्नाई कोटाडिया) (क) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों की चालू केन्द्रीय योजनाओं की संख्या निम्नलिखित है :-

	सड़क	पुल
राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	136	53
आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की सड़कें	—	—
केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.)	1	—

इसके अतिरिक्त 1990-91 के दौरान निम्न संख्यक योजनाओं का अनुमोदन किया गया है :-

राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास	15	—
आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की सड़कें	—	—
केन्द्रीय सड़क निधि	—	—

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए 21.00 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है जिसमें चल रहे कार्य और चालू वित्त वर्ष में अनुमोदित कार्य शामिल हैं। आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की योजना के अंतर्गत कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियां राज्य के लिए अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत विगत में रिलीज की गई निधियों, प्रचालनात्मक स्वीकृतियों की बकाया राशि और वज्रगत प्रावधान को ध्यान में रखकर रिलीज की जाती है। उपर्युक्त मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार को हकदारी के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आने वाले कार्य के लिए 1990-91 के दौरान आवंटन हेतु 50.00 लाख रु. की राशि निर्धारित की गई है।

मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालयों में तारघर की सुविधा

787. श्री राधा किशोर मालवीय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने ऐसे जिला मुख्यालय हैं जहां तारघर की सुविधा है; और

(ख) क्या सरकार ने एक निश्चित अवधि के अन्दर सभी जिला मुख्यालयों में तारघर खोलने का व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री और संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) मध्य प्रदेश के सभी 45 जिला मुख्यालयों में तारघर सुविधा मुहैया करवा दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नये डाकघर तथा शाखा डाकघरों का खोला जाना

788. श्री राधा किशत सालवीय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में कितने नये डाकघर तथा शाखा डाकघर खोले जाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(ख) इन डाकघरों तथा उनके कर्मचारियों पर खर्च की जाने वाली राशि का राज्यवार व्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री और संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 1000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 200 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव था। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के मानदण्डों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के सहयोग से संशोधित किया जा रहा है। जब तक मौजूदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक राज्यवार डाक नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। नए मानदण्ड निर्धारित हो जाने के बाद बजटीय प्रावधानों सहित राज्यवार व्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। संयोग से योजना आयोग ने डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदित कर दिया है जिसके अन्तर्गत नए डाकघर खोलने का कार्यक्रम

भी आ जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद की रिपोर्ट जनवरी, 1991 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाने की संभावना है।

Procedure for environment clearance

789. SHRI JITENDRABHAI LABH-SHANKER BHATT: Will the Minister Of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have submitted a set of proposals for rationalisation of environment clearance procedures which aim at "expanding the role of the Ministry" as reported in the Deccan Herald of 1st September, 1990; and

(b) if so, the details of improved procedure for environment clearance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA. GANDHI): (a) and (b) Proposals for rationalisation of environmental impact assessment procedure have been under consideration with the following salient features: —

- Making environmental impact assessment a statutory requirement;
- Uniform coverage of both private as well as public sector projects;
- Delegation of powers for environmental clearance of certain categories of projects to state agencies.

The primary objective of these proposals is to rationalise the procedure rather than expand the role of the Ministry.

मंडल आयोग के प्रतिवेदन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों को हुई क्षति

790. श्री प्रभाकर राव कलवला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने के विरोध में छात्रों द्वारा किए